मेहनतकशों का पैग़ाम — मेहनतकशों के नाम

मज़दूर मोर्चा

पाक्षिक

Email : mazdoormorcha@yahoo.co.in
www.mazdoormorcha.com

Postal Reg. No. L/H.R/FBD/463-06 /R.N.I. No. 66400/97

श्रमिकों की सत्ताईस नहीं पचासों हजार करोड़ की रकम है प्रधानमंत्री जी — 3

अवैध लूट के लिए अवैध निर्माण कराता है नगर निगम — 5

भगवा का विकल्प क्या कांग्रेस का संकट — 6

पटाखा बाजार अग्निकांड के दोषी 'ढूंढ़' रहे हैं दोषियों को — 8

वर्ष 27 | अंक 24 | फरीदाबाद, शनिवार, 1-15 नवम्बर 2014 | फोन : - 9999595632 | ₹ 2

हुड्डा गया भाड़ में, चौटाला तिहाड़ में

मनोहर लाल खट्टर टिकेगा या बिकेगा, भ्रष्टाचार के पहाड़ में

मनोहर लाल खट्टर को ईमानदारी के बड़े.बड़े फतवों के साथ नरेन्द्र मोदी और भाजपा ने हरियाणा के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया है। भ्रष्टाचार के चलते भूपेन्द्र हुड्डा को हरियाणा की जनता भाड़ में भेज चुकी है। राज्य में भ्रष्टाचार के दूसरे बड़े स्तंभ ओम प्रकाश चौटाला को वापस तिहाड़ जाना पड़ा है। मुख्यमंत्री खट्टर का रास्ता भी भ्रष्टाचार के पहाड़ को लांघ कर ही बनता है। सर्वविदित है कि हरियाणा के शीर्ष भाजपाईयों के मुंह में भी भ्रष्टाचार का खून उसी तरह लगा हुआ है जैसा कांग्रेसियों और दूसरों के। यहां तक कि हरियाणा में तो संघी भी छोटे-मोटे मुंह मारने से बाज़ नहीं आते। लिहाजा सोनिया के दामाद पर भ्रष्टाचार की सारी गाज गिराकर पल्ला झाड़ने के दिन अब लद गयेए और मोदी व खट्टर को अपनी पारी में हरियाणा में कुछ कर दिखाने की शुरुआत तुरंत करनी होगी।

मजदूर मोर्चा, चंडीगढ़ ब्यूरो

ठीक गुरू नरेन्द्र मोदी की ही तरह चेले मनोहर लाल खट्टर ने भी ज्योतिषियों से पंचांग दिखवा कर और 'शुभ मुर्हूत' निकलवा कर, दिनांक 26.10.14 को प्रात: 11.00 बजकर 23 मिनट पर हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण की। खट्टर के नाम पर मितव्ययिता के दावे तो खूब किये जा रहे हैं, पर राजभवन में सादगी से शपथग्रहण करने की अपेक्षा करीब एक करोड़ की (सरकारी) लागत से संपन्न एक भव्य समारोह में यह औपचारिकता पूरी की गयी।

बेशक भाजपा, हरियाणा में पहली बार अपने बल-बूते पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुई हो, लेकिन इससे पहले सांझा सरकारों में, चाहे वे चौटालों की रही हों या बंसीलाल की, भाजपाईयों की चाल-चरित्र व कार्यशैली हरियाणावासी खूब अच्छी तरह से देख चुके हैं। पुराने अनुभवों को याद करके लगता नहीं कि खट्टर सरकार पहले से कुछ बेहतर कर पायेगी। खट्टर खुद बेशक परिवार एवं मोहमाया के बंधनों से मुक्त हों, लेकिन वे भाजपाई तो मुक्त नहीं हैं जिन्होंने सत्ता हथियाने के लिए अंधाधुंध पानी की तरह पैसा बहाया हो। माना कि खट्टर के पास न कोई ज़मीन-जायदाद है और हो सकता है उन्हें धन दौलत से भी कोई लगाव न हो, परन्तु भाजपा को चुनाव जिताने के लिए जिन लोगों ने मोटी रकमें खर्च की हैं वे तो मुनाफे सहित अपने धन की वापसी चाहेंगे ही। और जिन हारने व जीतने वाले उम्मीदवारों ने 20 से 40 करोड़ तक खर्च कर दिये हैं वे क्या अगले पांच साल तक बैठे केवल हरि भजन करते रहेंगे?

फरीदाबाद के कृष्णपाल तथा विपुल गोयल जो अब तक भूपेंदर हुड्डा के सहारे सी.एल.यू. का धंधा चला रहे थे, अब अपनी सरकार आने पर बंद कर देंगे? विपुल गोयल जो विधायक बनने से पहले सत्ता की दलाली का धंधा करते थे और जिस धंधे की बदौलत वे अपना चुनाव जीतने के लिए अंधाधुंध पैसा बहा सके, क्या अपनी सरकार आने पर संन्यास ले लेंगे? दरअसल यह राज़ किसी से छिपा नहीं है कि सत्ता प्राप्ति के लिये किया जाने वाला खर्च एक प्रकार का निवेश होता है, जिसके बदले जीतने वाले तो मोटी लूट कमाते ही हैं, दाल-दलिया तो हारने वाले भी नहीं छोड़ते, छोटी-मोटी दलाली तो वे भी कर ही लेते हैं, और तो और खर्चा पानी तो विपक्षी दल वाले भी निकाल ही लेते हैं। इन हालात में खट्टर साहब कैसे राज्य को भ्रष्टाचार से मुक्त कर पायेंगे?

कांग्रेस मुक्त करना तो इसलिए संभव हो गया कि जनता कांग्रेसी सरकार द्वारा बड़े पैमाने पर फैलये गये भ्रष्टाचार से त्रस्त थी और विकल्प के नाम पर भाजपा को वोट दे गयी। हुड्डा के दौर में सरकार का हर छोटे से छोटा तथा बड़े से बड़ा कार्यालय भ्रष्टाचार के नये-नये कीर्तिमान बनाने में जुटा था। किसी भी उच्चाधिकारी का अपने मातहत कर्मचारी पर कोई नियन्त्रण नहीं था, क्योंकि जो उच्चाधिकारी अपने स्तर पर मोटे डाके मार रहा हो वह अपने आधीनस्थों को कैसे नियन्त्रित कर सकता है? इसके अलावा हर छोटे-बड़े अधिकारी का तार सीधे सत्ता के किसी न किसी बड़े स्तंभ से भी जुड़ा होता है, इसलिए भी कोई किसी की परवाह नहीं करता।

खट्टर के सामने सवाल यह पैदा होता है कि चाहें भी तो ईमानदार अधिकारी कर्मचारी लायें कहां से? फेंटने को तो ताश के वही 52 पत्ते हैं। इन्हीं को इधर से उधर किया जा सकता है। इनमें से जो कोई-कोई ईमानदार हैं भी तो क्या उनकी सिफारिश करने वाला कोई राजनेता मिलेगा? जी नहीं, खट्टर पार्टी के राजेनता भी तो केवल उन्हीं की सिफारिश करेंगे जो लूट का माल खायें भी और खिलायें भी। साथ में उनके इशारों पर उलटे-सीधे काम भी करें। इसी प्रवृत्ति के चलते तमाम सरकारी महकमों में पुराने लुटेरे अफसरों की जगह नए अफसर तो आ जायेंगे, लेकिन जनता की लूट ज़्यों की त्यों जारी रहेगी। विभागीय अकर्मण्यता व हरामखोरी भी ज्यों की त्यों जारी रहेगी ही।

खट्टर भी बने लाल, यानी वही हड्डी वही खाल!

क्या बंसीलाल, देवीलाल व भजनलाल की परम्परा को आगे बढ़ाते हुए मनोहरलाल खट्टर ने भी 'लाल' बनने की शुरुआत कर दी है? मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही नाम के आगे से खट्टर हटाकर सिर्फ 'लाल' रखने से क्या संकेत दिये गए हैं। पंजाबी होना या दिखाना तो कोई पाप नहीं, हां सिर्फ पंजाबियों का मुख्यमंत्री बनकर काम करना, जैसे पहले करते थे, जरूर पाप है। तो नाम बदलने से नहीं काम बदलने से बात बनेगी खट्टर साहब!

मंत्रीमंडल गठन के तीन दिन बाद तक भी खट्टर अपने मंत्रियों के बीच विभागों का वितरण नहीं कर पाये। सी.एम. पद के तमाम दावेदारों ने हाई कमांड के दबाव में खट्टर को मुख्यमंत्री तो स्वीकार कर लिया परन्तु उनकी अकड़ अभी कायम है। इसी के चलते केन्द्रीय मंत्री राव इन्द्रजीत तो अपने समर्थकों सहित शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करने वाले थे। आखिरी वक्त पर वे इसमें शामिल होने को राजी हुए। नंबर दो रामबिलास शर्मा की महत्वाकांक्षा का आलम यह है कि उन्हें लूट व ऐयाशी के बड़े महकमों से तसल्ली नहीं हुई, उन्हें गृह विभाग भी चाहिए ताकि चौधर दिखे भी। सर्वविदित है कि पुलिस एवं गुप्तचर विभाग वाले इस मंत्रालय को हरियाणा में सी.एम. सदैव अपने पास ही रखते आये हैं। गुप्तचर विभाग से तमाम सूचनाओं तथा पुलिस विभाग की लाठी के द्वारा ही प्रत्येक मुख्यमंत्री राज्य की जनता को हांक पाते हैं। यदि खट्टर ने यही रामबिलास को सौंप दिया होता तो फिर वे चंडीगढ़ में छनकने ही बजाते।

अन्य मलाईदार महकमों के लिए भी खासी मारामारी के चलते खट्टर दिल्ली दरबार की शरण में पहुंचे। यानी दिल्ली दरबार ही, आपाधापी एवं झपटमारी में उलझे इन मंत्रियों पर अंकुश लगा पाने में समर्थ है। ऐसे में खट्टर रोजमर्रा का कामकाज कैसे चला पायेंगे? यहां तो इस तरह के तमाशे हर रोज ही होने वाले है। क्या हर बात के लिए खट्टर जी दिल्ली की उड़ान भरा करेंगे? लब्बो-लुबाब यह कि हरियाणा ने नाम के 'लाल' तो कई देख लिए, अब काम के 'लाल' बन कर दिखाओ तो जानें खट्टर जी।

ख़बर दार

जे.एन.यू. में 'हिंदुत्व' के नाम पर ए.बी.वी.पी. का जनजातीय छात्रों पर हमला

दिल्ली (म. मो.) स्वयं को जनतन्त्र और वैचारिक स्वतन्त्रता की ठेकेदार बतानेवाली भाजपा की छात्र शाखा ए.बी.वी.पी. ने जनजातीय (ट्राइबल्स) व पिछड़े छात्रों के एक कार्यक्रम पर हिंसक हमला करके इसे रोकने की कोशिश की। हर साल की तरह इस साल भी जे.एन.यू. की ऑल इन्डिया बैकवर्ड स्टूडेन्टस फेडरेशन ने 9 अक्टूबर को कावेरी हास्टल के मैस में महिषासुर शहादत दिवस का आयोजन किया था। इस अवसर पर एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया था। 'कल्चरल रीइन्टरप्रेटेशन' (सांस्कृतिक पुनर्व्याख्या) नाम से इस कार्यक्रम की बाकायदा प्रशासन से इजाजत भी ली गई थी।

लेकिन केन्द्र में बी.जे.पी. सरकार होने के नशे में चूर और जे.एन.यू. में अपनी ताकत बढ़ाने को आतुर ए.बी.वी.पी. ने इस कार्यक्रम को धार्मिक उन्माद भड़काकर रोकने की पुरजोर कोशिश की। पहले तो विश्वविद्यालय प्रशासन से इसके खिलाफ शिकायत की गई कि इस कार्यक्रम से उनकी धार्मिक भावनायें आहत होंगी इसलिए इसको रोका जाय। लेकिन वैचारिक स्वतन्त्रता के पक्षधर प्रशासान ने जब इसको रोकने से मना कर दिया तो उन्होंने भाजपा की जरखरीद पुलिस में शिकायत की। यही नहीं मुट्ठी भर छात्रों को लेकर उन्होंने कावेरी मैस पर हमला कर दिया। नारेबाजी की गई और उससे भी बात नहीं बनी तो जबरदस्ती अन्दर घुसकर अन्य छात्रों को पीटा और मैस में तोड़फोड़ की। देर रात 'वफादार' पुलिस ने ए.बी.वी.पी. की

सवाल यह नहीं है कि महिषासुर राजा था या नहीं और दुर्गा देवी थी या नहीं। यह सवाल उन्होंने खड़ा भी नहीं किया था। सवाल तो यह है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद किसी भी विषय या घटना पर भिन्न विचार रखने वालों को बोलने दिया जाय या नहीं। क्या ए.बी.वी.पी. द्वारा दिखाई इस तरह की दादागिरी से जे.एन.यू. में वैचारिक स्वतन्त्रता रह पायेगी? क्या यह पाठ्य-पुस्तकों में जहर बोने वाले संघी दीनानाथ बत्रा की तरह अपने साम्प्रदायिक ओर कट्टरपंथी विचारों को थोपने का हिंसात्मक रास्ता नहीं है?

शिकायत के आधार पर फारवर्ड प्रैस, जिसने इस कार्यक्रम के पोस्टर छापे थे, उसके एक ड्राइवर प्रकाश और मार्किटिंग मैनेजर हाशमी हुसैन को गिरफ्तार कर लिया। उन पर साम्प्रदायिक वैमनस्य फैलाने का आरोप लगाया गया।

ध्यान रहे कि यह कार्यक्रम जे.एन.यू. में पिछले कई सालों से आयोजित होता रहा है। ए.आई.बी.एस.एफ. के अनुसार महिषासुर कोई राक्षस न होकर ट्राइबल्स का एक लोकप्रिय और बलशाली राजा था। इसको मारने में असमर्थ विरोधियों ने छल से इसको मारने के लिए दुर्गा को भेजा क्योंकि महिषासुर स्त्रियों पर हाथ नहीं उठाता था। अपने दृष्टिकोण का विस्तृत विवरण 'जातीय व्यवस्था और मिथकों का संघर्ष' नामके पर्चे में इन्होंने दिया है।

सवाल यह नहीं है कि महिषासुर राजा था या नहीं और दुर्गा देवी थी या नहीं। यह सवाल उन्होंने खड़ा भी नहीं किया था। सवाल तो यह है कि मोदी के सत्ता में आने के बाद किसी भी विषय या घटना पर भिन्न विचार रखने वालों को बोलने दिया जाय या नहीं। क्या ए.बी.वी.पी. द्वारा दिखाई इस तरह की दादागिरी से जे.एन.यू. में वैचारिक स्वतन्त्रता रह पायेगी? क्या यह पाठ्य-पुस्तकों में जहर बोनेवाले संघी दीनानाथ बत्रा की तरह अपने साम्प्रदायिक ओर कट्टरपंथी विचारों को थोपने का हिंसात्मक रास्ता नहीं है? इसके बाद ए.बी.वी.पी. ने लगातार कई दिन धरना-प्रदर्शन करके जे.एन.यू. के छात्रों को भी हिन्दू और हिन्दू विरोधी में बांटने की कोशिश की। मुजफ्फरनगर और हाल में दिल्ली में त्रिलोकपुरी में दंगे भड़काने की कोशिश में बी.जे.पी. सफल रही है। यह बताता है कि मोदी और शाह के गैंग ने सारे देश को अपनी तरह का हिन्दू बना छोडने की मुहिम अभी छोड़ी नहीं है। देखना यह है कि क्या जे.एन.यू. इस धारा को परास्त करके वैचारिक स्वतन्त्रता का झण्डा बुलन्द रख पायेगा।

श्रममंत्री के कान पर जूं रेंगी

लाज़िम है कि हम भी देखेंगे.....

फरीदाबाद (म.मो)। ईएसआई निगम द्वारा चिकित्सा सेवा के नाम पर मज़दूरों से किये जा रहे क्रूर मजाक के विरूद्ध 'मज़दूर मोर्चा' द्वारा उठाई गयी आवाज आखिरकार केन्द्रीय श्रममंत्री के कानों तक पहुंच गयी। इसके परिणामस्वरूप श्रममंत्री नरेन्द्र सिंह तौमर ने अपने वरिष्ठ अधिकारियों की एक आपात मीटिंग बुलाई जिसका ब्योरा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी प्रैस विज्ञप्ति में है जिसे ज्यों का त्यों प्रकाशित किया जा रहा है:-

कर्मचारी राज्य बीमा निगम के विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा करते हुए केन्द्रीय श्रम और रोजगार, इस्पात एवं खनन मंत्री श्री नरेन्द्र सिंह तौमर ने परियोजना प्रभारियों को प्रेरित किया कि वे इन परियोजनाओं में हो रहे विलंब के लिए उत्तरदायी समस्याओं का पता लगाएं तथा उन्हें हल करने के लिए एक कड़ी समय सीमा निर्धारित करें। उन्होंने सभी परियोजना प्रभारियों को यह निर्देश दिया कि यदि वे समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे तो महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम को अवगत कराएं और उसके बाद मंत्रालय को। उन्होंने परामर्श दिया कि जहां कहीं संभव हो कार्यप्रणाली से समझौता किए बिना परियोजना में तड़क-भड़क/आंडम्बर को कम किया जाए।

मंत्री महोदय ने परियोजना प्रभारियों को परामर्श दिया कि वे प्रत्येक परियोजना के लिए पृथक रूप से परिशोधित समय-सीमा तथा मध्यवर्ती लक्ष्य निर्धारित करे और निर्माण एजेंसियों एवं वास्तु तथा अभियांत्रिकी एजेंसियों की उपस्थिति में प्रत्येक परियोजना में की गई प्रगति की मासिक समीक्षा करें। यदि निर्माण एजेंसियां परियोजनाओं को पूर्ण करने में लापरवाह पाई जाती है तो उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए और उन्हें उनके साथ अंतिम बैठक करने क लिए बुलाया जाए। यदि आवश्यक हो तो संविदा को समाप्त कर दिया जाए। उन्होंने बल दिया कि कार्य में गति लाई जाए ताकि वर्ष 2015-16 से, जहां तक हो सके, अधिकतम संख्या में नए चिकित्सा महाविद्यालय प्रारंभ हो जाएं।

उन्होंने इस बात का भी संज्ञान लिया कि इस समय लगभग 50 परियोजनाओं पर काम चल रहा हैं जिसमें से 21 चिकित्सा शिक्षा परियोजनाएं, 15 अस्पताल परियोजनाएं तथा 14 अन्य परियोजनाएं हैं इसके अतिरिक्त 48 नई परियोजनाएं प्रक्रियाधीन है।

इस बैठक में सुश्री गौरी कुमार सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्री अनिल कुमार अग्रवाल, महानिदेशक, कर्मचारी राज्य बीमा निगम तथा श्री ए.के. सिन्हा, अपर सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय भी मौजूद थे।

श्रम मंत्री की इस कार्यवाही का निक्कमे अफ़सरों पर क्या असर होता है और वे कैसे काम को आगे चलाते हैं, लाजिम है कि हम भी देखेंगे.....